[2014] 11 एस. सी. आर 286

मेसर्स राम बरई सिंह और कंपनी

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(दीवानी अपील सं. 11465/2014)

17 दिसंबर, 2014

[एम. वाई. एक्बाल और शिवा कृति सिंह, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1951-अनुच्छेद 226-अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका विचार करने पर प्रत्यर्थी द्वारा अनापूर्ति लिया गया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा योग्यता के आधार पर दी गई रिट याचिका-प्रत्यर्थी द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर दरकिनार करते हुए एल.पी.ए. की अनुमति दी कि मध्यस्थता खंड के माध्यम से वैकल्पिक आय का सहारा लिया जा सकता था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:रिट याचिका के माध्यम से संवैधानिक उपाय हमेशा एक पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध होता है और पक्ष के बीच एक समझौते में मध्यस्थता खंड; इस तथ्यों में एक रिट याचिका को "बनाए रखने योग्य नहीं" नहीं बना सकता है-तथ्यों पर, कोई मौजूदा समझौता नहीं था क्योंकि काम पूरा हो चुका था और भुगतान पहले ही किया जा चुका था, और रिट याचिका में अंतिम निर्णय योग्यता के आधार पर दिया गया था-इस प्रकार, खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया 1.1 रिट याचिका के माध्यम से एक संवैधानिक उपाय हमेशा एक पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध होता है और पक्षों के बीच में एक मध्यस्थता खंड वास्तव में एक रिट याचिका को "बनाए रखने योग्य नहीं" नहीं बना सकता है जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है। वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता निश्चित रूप से एक रिट अदालत द्वारा उचित मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए एक अनुमेय आधार है। लेकिन एक बार उत्तरदाताओं ने वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने पर आपत्ति नही जताया था। योग्यता के आधार पर दिए गए अंतिम निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता है और केवल खंडपीठ द्वारा यह ध्यान में रखते हुए अलग नहीं किया जा सकता है कि मध्यस्थता खंड के माध्यम से एक वैकल्पिक उपाय का सहारा लिया जा सकता था। तथ्यों पर, कोई मौजूदा समझौता नहीं था क्योंकि काम पूरा हो चुका था और भुगतान बहुत पहले ही कर दिया गया था। इस प्रकार, अपील के तहत आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। [कंडिका 12,13,14) [291-0-G; 292-सी]

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) सी लिमिटेड 1996 (4) पूरक एससीआर 762:(1996) 6 एस.सी.सी. 22; एबीएल:इंटरनेशनल लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम निर्यात ऋण गारंटी भारतीय निगम लिमिटेड और अन्य। (2004) 3 एस. सी. सी. 553-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

1996 (4) पूरक एससीआर 762	संदर्भित किया गया है।
(2004) 3 एस. सी. सी. 553	संदर्भित किया गया है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः2014 की दीवानी अपील सं. 11465।

2009 के एल. पी. ए. सं. 762 में पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए गौरव अग्रवाल।

उत्तरदाताओं के लिए मनीष कुमार (गोपाल सिंह के लिए)।

न्यायालय का निर्णय शिव कीर्ति सिंह, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

निर्णय

1. पक्षों को सुना। अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2009 की एल. पी. ए. संख्या 762 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 12.01.2011 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें इसमें प्रत्यर्थियों द्वारा पेश की गई लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति दी गई थी और 2008 की सी. डब्लू. जे. सी. संख्या 10173 वाली रिट याचिका में 18 फरवरी, 2009 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को एकमात्र इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पक्षकारों के बीच एक समझौते में एक मध्यस्थता खंड था और चूंकि इस तरह के वैकल्पिक उपचार का अपीलार्थी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया था, इसलिए रिट याचिका ही विचारणीय नहीं थी।

3. अपीलार्थी के विद्वत वकील ने तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी खंडपीठ के पूर्वोक्त आदेश की आलोचना की है। कानून के बारे में, यह तर्क दिया गया था कि रिट याचिका को विचारणीय नहीं माना जा सकता था, और अधिक जब दूसरे पक्ष द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। तथ्यों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि खंड पीठ द्वारा देखे गए समझौते में निःसंदेह एक मध्यस्थता खंड था जो किसी भी पक्ष को समझौते से उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में संबंधित अधीक्षक अभियंता द्वारा मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए हकदार बनाता है, लेकिन खंड पीठ इस बात पर ध्यान देने में विफल रही कि समझौता अब अस्तित्व में नहीं रहा

क्योंकि काम बहुत पहले पूरा हो गया था और फरवरी 1992 में 9.53 लाख रुपये की राशि श्रम वृद्धि लागत के कारण भुगतान सहित भुगतान किया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी के अनुसार, 06.02.1989 दिनांकित समझौते ने स्वयं कार्य किया था और यह बहुत बाद में हुआ कि एक विवाद उत्पन्न हुआ जब प्रत्यर्थी अधिकारियों ने एक लंबी अवधि के लिए अपीलार्थी की 30 लाख रुपये की प्रतिभूति राशि रोक रखी। लगातार मांग पर, प्रतिभूति राशि में से 20 लाख रुपये दिसंबर 2002 में 10 वर्षों के बाद और वह भी बिना किसी ब्याज के वापस कर दिए गए थे। उस स्तर पर अपीलार्थी को पता चला कि अभियंता-इन-चीफ ने 9.06.2001 दिनांकित आदेश द्वारा अपीलार्थी से 9 लाख रुपये की वसूली करने का आदेश दिया था। जिसका भुगतान श्रम वृद्धि लागत के कारण काफी पहले कर दिया गया था।

4. अपीलार्थी ने प्रतिभूति जमा में अनावश्यक विलंब पर ब्याज का दावा करने के लिए और श्रम वृद्धि लागत की वसूली के निदेश के विरुद्ध 2005 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3686 वाली एक रिट याचिका प्रस्तुत की। प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थता खंड की दलील नहीं दी और यह कि सुरक्षा राशि के भुगतान में देरी के कारण 12% ब्याज की अनुमति देते हुए 20.09.2006 को रिट याचिका का निपटान किया गया। श्रम वृद्धि लागत का मुद्दा संबंधित इंजीनियर-इन-चीफ के पास वापस भेज दिया गया, जिसे एक निश्चित अवधि के भीतर अपीलकर्ता या उसके प्रतिनिधि को सुनने के बाद एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी को अपना उपचार मांगने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी यदि वह इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित था।

5. प्रत्यर्थियों ने 2006 की संख्या 877 वाली एक लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी, जिसमें भी उन्होंने मध्यस्थता खंड के माध्यम से वैकल्पिक उपचार का मुद्दा नहीं उठाया।एलपीए का निपटान 11.12.2007 को निम्नलिखित निर्देश के साथ किया गयाः

> ".....चूंकि मामला प्रतिप्रेण पर चल रहा है, इसलिए राज्य को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर नए सिरे से विचार करना

होगा और इसलिए, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, निर्देश प्रतिप्रेण के आदेश के लिए समायोजन होगा।तथापि, दोनों पक्षों द्वारा ब्याज के भुगतान के प्रश्न का पालन किया जाएगा। बिहार राज्य द्वारा प्रश्न का अंतिम अवधारण।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मामले की जांच की जाएगी और राज्य द्वारा इसे तेजी से फिर से निर्धारित किया जाएगा।"

6. इंजीनियर-इन-चीफ ने अपीलार्थी के खिलाफ 21.05.2008 को एक नया आदेश पारित किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा मामले के गुण-दोष और साथ ही साथ अपीलार्थी के अनुसार इंजीनियर-इन-चीफ की अधिकारिता से संबंधित अपने अभ्यावेदन में उठाए गए विभिन्न आधारों और आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, जिसकी इस मुद्दे में कोई भूमिका नहीं थी, जिसे कार्यकारी इंजीनियर और अधीक्षक इंजीनियर के स्तर पर अंतिम रूप दिया जाना था। अपीलार्थी ने 2008 की सी. डब्लू. जे. सी. संख्या 10173 वाली रिट याचिका के माध्यम से इंजीनियर-इन-चीफ के आदेश को चुनौती दी, जिसे एक तर्कसंगत आदेश द्वारा 18 फरवरी, 2009 को विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। ऐसा कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया, लेकिन दिनांक 06.02.1989 के समझौते में एक मध्यस्थता खंड के माध्यम से वैकल्पिक उपचार के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई।

7. विद्वत एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को दिनांक 21.05.2008 के इंजीनियर-इन-चीफ के आदेश को रद्द करके मंजूर किया। अदालत ने पाया कि इंजीनियर-इन-चीफ ने वर्ष 2008 में राज्य की देनदारी को पूरा करने के लिए श्रम वृद्धि लागत के रिफंड के साथ ब्याज की मांग की थी। लगभग 10 वर्ष की देरी के बाद प्रतिभूति जमा के रिफंड पर ब्याज का भुगतान करना। इस प्रकार प्रत्यर्थियों की कार्रवाई को बाहरी कारणों से अभिनिर्धारित किया गया था और इसके

वास्तविक भुगतान से एक लंबे अंतराल के बाद श्रम वृद्धि लागत पर आपत्ति मनमानी और अनुचित अभिनिर्धारित की गई थी।

8. विद्वत एकल न्यायाधीश के 18 फरवरी, 2009 के पूर्वोक्त आदेश को खंड पीठ द्वारा पहले से ही नोटिस किए गए आधार पर अपील के तहत आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

9. हम अपीलकर्ता के मामले से सहमत हैं कि खंडपीठ पहले मुकदमेबाजी के इतिहास सहित प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देने में विफल रही।यह भी ध्यान देने में विफल रहा कि समझौते ने स्वयं बहुत पहले और मुकदमेबाजी के पहले दौर में और साथ ही वर्तमान दौर में प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थता खंड के आधार पर कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई।

10. खंडपीठ ने इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ब्रीज और रुफ कं. (इंडिया) लिमिटेड (1996) 6 एससीसी 22 और एबीएल के मामले में इंटरनेशनल लिमिटेड और एक और वी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य (2004) 3 एससीसी 553 आने के लिए। इस निष्कर्ष तक कि जहां संविदा स्वयं यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकारिता का उपयोग करने से इनकार करने के लिए एक अच्छा आधार है और यह कि न्यायालय मध्यस्थता के माध्यम से उपचार का आह्वान किए बिना अन्य उपचार का सहारा लेने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि निश्चित रूप से, विवाद के दोनों पक्ष विवाद समाधान के किसी अन्य तरीके पर सहमत न हों।

11. हमारे सुविचारित विचार में, पूर्वोक्त दो विनिश्चयों में गुणागुण पर जाने और वैकल्पिक उपचार के आधार पर अपीलीय चरण पर रिट याचिका को खारिज किए बिना विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने की आवश्यकता नहीं थी जब प्रत्यर्थियों द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष या लेटर्स पेटेंट अपील के ज्ञापन में भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

12. हमारे विचार में, रिट याचिका के माध्यम से एक संवैधानिक उपचार हमेशा व्यथित पक्षकार को उपलब्ध होता है और पक्षकारों के बीच किसी करार में एक माध्यस्थम खंड स्वयमेव रिट याचिका को 'अनुरक्षणीय नहीं' नहीं बना सकता है जैसा कि खंड न्यायपीठ द्वारा गलत अभिनिर्धारित किया गया है। वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता निश्चित रूप से रिट अदालत द्वारा उचित मामलों में अपनी अधिकारिता का उपयोग करने से इनकार करने के लिए एक स्वीकार्य आधार है। लेकिन एक बार जब प्रत्यर्थियों ने वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को स्वीकार करने पर आपत्ति नहीं जताई थी, तो अंतिम निर्णय दिया गया। केवल खंडपीठ द्वारा यह ध्यान दिए जाने पर कि माध्यस्थम् खंड के माध्यम से एक वैकल्पिक उपचार का सहारा लिया जा सकता है, गुणागुण को दोष नहीं दिया जा सकता और अपास्त नहीं किया जा सकता है।

13. हमारे विचार में, अपीलार्थी के विद्वत वकील ने उपरोक्त दोनों तथ्यों पर अपील के तहत आदेश को रद्द करने के लिए एक मामला बनाया है, जो दर्शाता है कि कोई मौजूदा समझौता नहीं था क्योंकि काम पूरा हो चुका था और भुगतान पहले ही बहुत पहले कर दिया गया था और इस अपील में उठाए गए कानून के सवाल पर भी कि एक रिट याचिका के माध्यम से एक संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं माना जा सकता है और एक वैकल्पिक उपचार के कारण इसे बनाए रखना संभव नहीं है। यह रिट अदालत के लिए विचार करने के लिए है कि क्या एक उचित मामले में, रिट याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने के लिए दरकिनार कर दिया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन एक बार जब रिट याचिका पर विस्तार से सुनवाई की जाती है और गुण-दोष के आधार पर एक या दूसरे पक्ष के खिलाफ निर्णय लिया जाता है, तो इस तरह के निर्णय/आदेश को केवल इस आधार पर कानून के लिहाज से गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि रिट याचिका वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के कारण सुनवाई योग्य नहीं थी।

14. विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश द्वारा प्रतिबिंबित गुणों के आधार पर मामले पर विचार करने के बाद, हम इस अपील में पर्याप्त योग्यता पाते हैं और इसलिए

इसकी अनुमति दी जाती है। अपील के तहत आदेश को रद्द कर दिया जाता है और विद्वत एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दो महीने के भीतर भुगतान किए जाने वाले 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) की लागत के साथ वापस कर दिया।

[एम. वाई. इकबाल], न्यायमूर्ति

[शिव कीर्ति सिंह], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

17 दिसम्बर, 2014

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

आइटम नंबर 1 ए कोर्ट नंबर 10 सेक्शन Xvi

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिकॉर्ड कार्यवाही

अपील के लिए विशेष अनुमति हेतु याचिकाओं में 2014 की सिविल अपील संख्या 114658101/2011

मैसर्स राम बरई सिंह एंड कंपनी अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य और अन्य उत्तरदाता

तिथिः 17/12/2014 यह अपील आज निर्णय के लिए बुलाई गई थी।

प्रतिवादी के लिए श्री गौरव अग्रवाल, एडवोकेट

फॉर रेस्पोंडेंट श्री गोपाल सिंह, एडवोकेट

माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव कीर्ति सिंह ने माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. वाई. इकबाल और हिज लार्डशिप की पीठ का निर्णय सुनाया।

अवकाश की अनुमति दी गई।

अपील को हस्ताक्षरित शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाती है।

(सुखबीर पाल कौर) (इंदु पोखरियाल)

कोर्ट मास्टर कोर्ट मास्टर

(हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय फाइल पर रखा गया है)